YOJANASEWA.COM

https://yojanasewa.com

H-1B वीजा पर बड़ा एक्शन कॉग्निजेंट समेत कई कंपनियों पर लटकी तलवार!

विषय सूची (Table of Contents):

>> H-1B और PERM वीजा पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई क्या है पूरा मामला?...
>> धोखाधड़ी के खिलाफ व्यापक अभियान...
>> श्रम विभाग की योजनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल...
>> जांच के घेरे में कॉग्निजेंट समेत कई बड़ी कंपनियां, शुरू हुई सख्त कार्रवाई...
>> कॉर्पोरेट शाखाओं में मची हलचल...
>> सख्त कानूनी जांच की रूपरेखा...
>> अमेरिकी श्रम विभाग (OIG) का खुलासा वीजा आवेदनों में कैसे हुई धोखाधड़ी?...
>> फर्जी आवेदनों का खेल...
>> प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन...
>> उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान   करदाताओं के पैसे और अमेरिकी नौकरियों की हो...
>> अमेरिकियों के हितों की रक्षा पहली प्राथमिकता...
>> नीतिगत बदलावों का संकेत...
>> कम वेतन और शोषण विदेशी कामगारों के नाम पर कंपनियों के खेल का पर्दाफाश...
>> वेतन वापसी (Wage Clawback) जैसी जबरन व्यवस्था...
>> H-1B वीजा का मूल उद्देश्य क्या है और बड़ी कंपनियों ने इसका दुरुपयोग कैसे किया?...
>> कोटा और आवेदन की वर्तमान स्थिति...
>> यूएससीआईएस (USCIS) में बढ़ती शिकायतें...
>> भारतीय टेक प्रोफेशनल्स पर क्या पड़ेगा असर और ट्रंप प्रशासन का अगला कदम?...
>> ट्रंप प्रशासन की भावी योजनाएं...
>> क्या सावधानियां बरतनी होंगी?...
>> निष्कर्ष...
>> जनता के सवाल (FAQs)...

Latest Update 2026:अमेरिकी वीजा नीतियों को लेकर वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स (US) प्रशासन ने H-1B और PERM वीजा कार्यक्रमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस सख्त कदम के बाद आईटी सेक्टर और विदेशी नियोक्ताओं के बीच हड़कंप मच गया है।

H-1B और PERM वीजा पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई: क्या है पूरा

अमेरिकी श्रम विभाग ने विदेशी कामगारों के वीजा आवेदनों में बड़े पैमाने पर हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। यह मामला सीधे तौर पर उन कंपनियों और श्रम दलालों (Labour Brokers) से जुड़ा है, जो नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे थे।

धोखाधड़ी के खिलाफ व्यापक अभियान

मिलवौकी में दिए गए एक बयान के अनुसार, यह कार्रवाई अमेरिकी करदाताओं के पैसे की सुरक्षा के लिए की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य वीजा कार्यक्रमों के माध्यम से होने वाली जालसाजी को पूरी तरह से समाप्त करना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वे अमेरिकी कामगारों के हितों से समझौता नहीं करेंगे।

श्रम विभाग की योजनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल

जांच एजेंसियों का मानना है कि इस प्रकार की कथित अनियमितताओं के कारण श्रम विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की साख दांव पर लगी है। जिस तरह खेल जगत में बड़े प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि फीफा में बड़ा उलटफेर: अमेरिका की जीत, तुर्की वर्ल्ड कप से बाहर!की खबर चर्चा में रही थी, उसी तरह अमेरिकी नीति निर्माता अब आव्रजन व्यवस्था में बड़ा फेरबदल कर रहे हैं।

जांच के घेरे में कॉग्निजेंट समेत कई बड़ी कंपनियां, शुरू हुई

अमेरिकी श्रम मंत्रालय (Department of Labor) की इस ताजा कार्रवाई में आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कॉग्निजेंट (Cognizant) सहित कई अन्य बड़ी कंपनियों का नाम सामने आया है। इसके बाद से ही इन कॉर्पोरेट घरानों की विभिन्न शाखाओं में हड़कंप का माहौल है।

कॉर्पोरेट शाखाओं में मची हलचल

मंत्रालय द्वारा नाम उजागर किए जाने के बाद इन कंपनियों की आंतरिक विग्स और कानूनी टीमें अगली कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई हैं। कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने PERM और H-1B वीजा की शर्तो का उल्लंघन किया है।

सख्त कानूनी जांच की रूपरेखा

इन बड़ी कंपनियों की फाइलिंग हिस्ट्री और कर्मचारियों के डेटाबेस को खंगाला जा रहा है। जांच का दायरा केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑन-साइट वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। आने वाले दिनों में कंपनियों की एक ब्लैक लिस्ट भी सामने आ सकती है।

अमेरिकी श्रम विभाग (OIG) का खुलासा: वीजा आवेदनों में कैसे हु

अमेरिकी श्रम विभाग के अंतर्गत काम करने वाले ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल (OIG) ने इस जांच में चौंकाने वाले तौर-तरीकों (Modus Operandi) का खुलासा किया है। ओआईजी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह एक सुनियोजित नेटवर्क की तरह काम कर रहा था।

फर्जी आवेदनों का खेल

नियोक्ताओं और श्रम दलालों ने मिलकर कथित रूप से ऐसे पदों के लिए फर्जी आवेदन दाखिल किए जिनकी वास्तव में कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इन फर्जी आवेदनों के जरिए वीजा स्लॉट बुक किए गए, जिससे योग्य उम्मीदवारों को मौका नहीं मिल सका।

प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन

जैसे भारत में स्थानीय कानून एजेंसियां अवैध गतिविधियों पर नकेल कसती हैं, जिसका उदाहरण हाल ही में देखा गया जब एककिराना दुकान में टॉफी के साथ बिक रहा था गांजा और बीयर, पुलिस का छापा!जैसी घटना सामने आई थी, ठीक वैसे ही अमेरिकी फेडरल एजेंसियां अब श्रम कानूनों के उल्लंघनकर्ताओं पर कड़ी रेड और जांच कर रही हैं।

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान: करदाताओं के पैसे और अम

इस पूरे मामले पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संदिग्ध विदेशी जालसाजों और नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

अमेरिकियों के हितों की रक्षा पहली प्राथमिकता

जेडी वेंस ने आश्वस्त किया कि इस योजना के जरिए अमेरिकी नागरिकों के रोजगार और उनके आर्थिक हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उन्होंने इसे देश के भीतर चल रहे एक व्यापक धोखाधड़ी-विरोधी अभियान का हिस्सा बताया।

नीतिगत बदलावों का संकेत

यह बयान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में वीजा अप्रूवल की प्रक्रिया को और अधिक जटिल और पारदर्शी बनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय नीतियों और विदेशी रोजगार के इस बड़े बदलाव को समझने के लिए इच्छुक उम्मीदवारयूपीएससी पाठ्यक्रम 2026, आईएएस प्रारंभिक और मुख्यका संदर्भ ले सकते हैं, जहां वैश्विक संबंधों पर विस्तृत सामग्री उपलब्ध है।

कम वेतन और शोषण: विदेशी कामगारों के नाम पर कंपनियों के खेल क

जांच में यह भी सामने आया है कि विदेशी कामगारों को केवल अमेरिका लाने का साधन बनाया गया, जबकि वहां पहुंचने के बाद उनका आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा था।

वेतन वापसी (Wage Clawback) जैसी जबरन व्यवस्था

>> शोषण के तरीके:कंपनियों द्वारा विदेशी श्रमिकों को तयशुदा वेतन देने के बाद उनसे चुपके से पैसे वापस ले लिए जाते थे।

>> अमेरिकी कामगारों को नुकसान:बहुत कम वेतन पर बाहर से भारी संख्या में श्रमिक लाकर स्थानीय अमेरिकी कामगारों की मजदूरी दरों को कृत्रिम रूप से घटाया गया।

>> श्रम बाजार पर असर:इस प्रथा के कारण वास्तविक रूप से कुशल श्रमिकों को उचित वेतन मिलना बंद हो गया।

H-1B वीजा का मूल उद्देश्य क्या है और बड़ी कंपनियों ने इसका द

H-1B एक बेहद लोकप्रिय गैर-आप्रवासी (Non-Immigrant) वीजा कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति वेंस के अनुसार, इसका गठन अत्यंत कुशल पेशेवरों, जैसे वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और तकनीकी विशेषज्ञों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देने के लिए किया गया था।

कोटा और आवेदन की वर्तमान स्थिति

वर्तमान नियमों के तहत, प्रतिवर्ष नियमित कोटा 65,000 वीजा का होता है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी विश्वविद्यालयों से मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाले उच्च शिक्षित युवाओं के लिए 20,000 वीजा अलग से आरक्षित रखे जाते हैं।

यूएससीआईएस (USCIS) में बढ़ती शिकायतें

बड़ी कंपनियों द्वारा इस कार्यक्रम का दुरुपयोग करके अमेरिकी श्रमिकों की मजदूरी कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि इस दुरुपयोग को रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) में याचिकाएं दी जाती हैं, लेकिन अब इन याचिकाओं के भी गलत इस्तेमाल की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं।

भारतीय टेक प्रोफेशनल्स पर क्या पड़ेगा असर और ट्रंप प्रशासन क

चूंकि H-1B वीजा भारतीय आईटी इंजीनियरों और तकनीकी पेशेवरों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, इसलिए इस कार्रवाई का सीधा असर भारतीय कार्यबल पर पड़ना तय माना जा रहा है।

ट्रंप प्रशासन की भावी योजनाएं

वर्तमान ट्रंप प्रशासन इन सभी कमियों को दूर करने के लिए वीजा नियमों में बुनियादी बदलाव कर रहा है। आवेदनों की बारीकी से स्क्रूटनी की जा रही है और कंपनियों की जवाबदेही तय की जा रही है।

क्या सावधानियां बरतनी होंगी?

अब किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए Apply Online करने से पहले उम्मीदवारों और कंपनियों को अपनी पात्रता सूची (Eligibility List) और दस्तावेजों को पूरी तरह पारदर्शी रखना होगा। भविष्य में वीजा अप्रूवल का स्टेटस (Status) चेक करने की प्रक्रिया में और अधिक कड़े सुरक्षा मानक जोड़े जा सकते हैं।

निष्कर्ष

अमेरिकी श्रम विभाग (OIG) और ट्रंप प्रशासन की यह संयुक्त कार्रवाई कॉग्निजेंट जैसी कंपनियों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। H-1B और PERM वीजा के मूल स्वरूप को बहाल करने के लिए यह कदम जरूरी बताया जा रहा है। हालांकि, इससे जेन्युइन

भारतीय प्रोफेशनल्स को शुरुआती दौर में कुछ प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से इससे केवल वास्तविक प्रतिभाओं को ही लाभ मिलेगा और बाजार से फर्जी कंसल्टेंसी और दलालों का खात्मा होगा।

जनता के सवाल (FAQs)

अमेरिकी श्रम विभाग और ओआईजी ने वीजा आवेदनों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, फर्जी आवेदन दाखिल करने और विदेशी कामगारों के शोषण के खिलाफ सख्त कानूनी जांच शुरू की है।

इस कार्रवाई के तहत आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कॉग्निजेंट (Cognizant) समेत कई बड़ी कंपनियों और विदेशी संस्थाओं के नाम मुख्य रूप से सामने आए हैं।

कंपनियों पर फर्जी दस्तावेज जमा करने, विदेशी कामगारों से उनका वेतन वापस लेने (Wage Clawback) और कम वेतन देकर अमेरिकी नागरिकों के रोजगार को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं।

जेडी वेंस ने कहा कि H-1B वीजा वैज्ञानिकों और डॉक्टरों जैसे अत्यंत कुशल पेशेवरों के लिए था, लेकिन बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल स्थानीय अमेरिकी कामगारों की मजदूरी घटाने के लिए कर रही हैं।

इसका नियमित वार्षिक कोटा 65,000 है, जबकि अमेरिका से मास्टर डिग्री करने वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा आरक्षित रखे गए हैं।

हाँ, क्योंकि भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स इस वीजा का सबसे अधिक लाभ उठाते हैं। सख्त स्क्रूटनी और नियमों के कारण जेन्युइन आवेदकों को अधिक सतर्क रहना होगा।

ओआईजी (OIG) अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर जांच का लेटेस्ट अपडेट और दोषी नियोक्ताओं की लिस्ट जारी करता है, जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

हाँ, सभी आवेदक यूएससीआईएस (USCIS) के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने रसीद नंबर (Receipt Number) के माध्यम से लाइव एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

इसके लिए आपके पास एक वैध अमेरिकी नियोक्ता (Employer) होना आवश्यक है, जो माययूएससीआईएस (myUSCIS) पोर्टल पर आपके नाम का इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन फाइल कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करेगा।